



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 10, 2019/चैत्र 20, 1941

No. 249]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 10, 2019/CHAITRA 20, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2019

सं. 18/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 299(अ).—जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 7303 00 30 या 7303 00 90 के अंतर्गत आते हैं के मामले में अधिसूचना संख्या 15/1006/2012-डीजीएडी, दिनांक 04 सितम्बर, 2013, जिसे दिनांक 04 सितम्बर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल पर प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की थी;

और जहाँ कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्टूबर, 2013, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत इस विषयगत माल पर दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 से प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहाँ कि मैसर्स जिंदल सॉलिमिटेड के द्वारा दायर स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 12368/2018 के मामले में आए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 51/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 09 अक्टूबर, 2018,

जिसे सा.का.नि. 1012 (अ), दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उक्त विषयगत वस्तु पर प्रतिपाटन शुल्क को 09 अप्रैल, 2019 तक बढ़ा दिया था;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या फाइल संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 09 अक्तूबर, 2018, जिसे दिनांक 09 अक्तूबर, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था, के तहत रिव्यू जांच शुरू की थी;

और जहां कि उक्त रिव्यू जांच के पूरा हो जाने पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयात के बारे में अधिसूचना संख्या 7/18/2018-डीजीएडी, दिनांक 01 अप्रैल, 2019 जिसे दिनांक 01 अप्रैल, 2019, को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1, में प्रकाशित किया गया था अपने अंतिम निष्कर्षों को जारी किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने उक्त निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की जरूरत नहीं है और उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “डक्टाइल आयरन पाइप्स” के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को और आगे जारी रखने की सिफारिश नहीं की थी।

और जहां कि मैसर्स जिंदल सॉलिमिटेड द्वारा माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किए गए स्पेशल सिविल एप्लीकेशन संख्या 6896/2019 के मामले में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को दिए गए निर्णय में आदेश दिया है कि:

- “1) इस प्रक्रिया के अंतर्गत विवादित अंतिम निष्कर्ष पर अगली सुनवाई की तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
- 2) दिनांक 09/10/2018 की अधिसूचना के अंतर्गत प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाए जाने का जो आदेश दिया गया था उससे प्रतिवादी अर्थात् भारत संघ के द्वारा और आगे भी यथोचित अवधि तक बढ़ाया जाए जो कि दिनांक 09.04.2019 से एक महीने से कम न हो”।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाठित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 05 अप्रैल, 2019 को आए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अक्तूबर, 2013, जिसे सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 3 में अंक, अक्षर और शब्द “09 अप्रैल, 2019” के स्थान पर “09 मई, 2019” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. संख्या 354/3/2007-टीआरयू (पार्ट. I)]

रूचि विष्ट, अवर सचिव

नोट – प्रधान अधिसूचना संख्या 23/2013, सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 को सा.का.नि. 680 (अ), दिनांक 10 अक्तूबर, 2013 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 51/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 09 अक्तूबर, 2018, को सा.का.नि. 1012 (अ), दिनांक 9 अक्तूबर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i), के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th April, 2019

No. 18/2019-Customs (ADD)

G.S.R. 299 (E). —Whereas in the matter of Ductile iron pipes (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff items 7303 00 30 or 7303 00 90 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 15/1006/2012-DGAD, dated the 4th September, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 4th September, 2013, had recommended continuation of anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject country;

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed anti-dumping duty on the subject goods with effect from the 10th October, 2013 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013-Customs (ADD), dated the 10th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October, 2013;

And whereas, in pursuance of the Judgement dated the 26th September, 2018 of Hon'ble High Court of Gujarat in the matter of Special Civil Application No. 12368 of 2018, filed by M/s Jindal Saw Limited, the Central Government had extended the anti-dumping duty on the subject goods upto the 9th April, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 51/2018-Customs (ADD) dated the 9th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1012 (E), dated the 9th October, 2018;

And whereas, the designated authority had initiated the review investigation *vide* notification No. F.No.7/18/2018-DGAD, dated the 9th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 9th October, 2018, concerning imports of 'Ductile Iron Pipes' originating in or exported from China PR;

And whereas, on completion of review investigation, the designated authority issued final finding *vide* notification No. 7/18/2018-DGAD, dated the 1st April, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 1st April, 2019 concerning imports of 'Ductile Iron Pipes' originating in or exported from China PR and the designated authority *vide* the said findings concluded that continuation of anti-dumping duty is not warranted and did not recommend further extension of anti-dumping duty on import of 'Ductile Iron Pipes' originating in or exported from China PR.

And whereas, M/s Jindal Saw Limited filed a Special Civil Application No. 6896 of 2019 before the Hon'ble High Court of Gujarat and the Hon'ble High Court of Gujarat *vide* Judgement dated the 5th April, 2019, has ordered that-

"1) the final finding impugned in this proceeding may not be acted upon till the next date of hearing.

2) the extension of anti-dumping duty ordered under the notification dated 09/10/2018 be further extended by respondent-Union of India for appropriate period, not less than one month from 09/04/2019".

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 and in pursuance of the order of the Hon'ble High Court of Gujarat dated the 5th April, 2019, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 23/2013, Customs (ADD), dated the 10th October, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October, 2013, namely:-

In the said notification, in paragraph 3, for the figures, letters and words "9th April, 2019", the figures, letters and words "9th May 2019" shall be substituted.

[F. No. 354/3/2007-TRU (Pt. I)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 23/2013- Customs (ADD), dated the 10th October, 2013 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 680 (E), dated the 10th October, 2013 and subsequently amended *vide* notification No.51/2018-Customs dated the 9th October, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1012(E), dated the 9th October, 2018.